अगस्त में निर्यात 26 प्रतिशत बढ़ा

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 16 सितंबर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगस्त की ट्रेड दिल्ली, सिमने आए हैं. अगस्त 2020 में देश को व्यापार घाटा मामूली कमी के साथ 26.86 अरब डॉलर रहा. पिछले साल अगस्त में यह 27.2 अरब डॉलर था. खास बात यह रही कि इस दौरान भारत के निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि आयात की रफ्तार तुलनात्मक रूप से कम रही.

अगस्त में भारत का कुल निर्यात 26 फीसदी बढ़कर 43.81 अरब डॉलर पहुंच गया. एक साल पहले इसी महीने निर्यात 27.22 अरब डॉलर था. दूसरी ओर, आयात 14 फीसदी बढ़कर 70.04 अरब डॉलर रहा, जबकि अगस्त 2025 में यह 61.96 अरब डॉलर था. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों यानी अप्रैल से अगस्त के आंकड़ों पर नजर डालें तो निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है. इस अवधि में भारत का एक्सपोर्ट 17.85 फीसदी बढ़कर 215.91 अरब डॉलर हो गया. इसी अवधि में आयात भी तेजी से बढ़ा. अप्रैल-अगस्त के दौरान देश का आयात 18.21 फीसदी की वृद्धि के साथ करीब 363 अरब डॉलर रहा यानी इस वित्त वर्ष अब तक निर्यात के साथ-साथ आयात में भी मजबूत ग्रोथ बनी हुई है.

अमेरिका और यूरोप से मिल रहा सपोर्ट- भारतीय सामान की मांग कई प्रमुख विदेशी बाजारों में मजबूत बनी हुई है. अमेरिका और यूरोपीय संघ के अलावा ब्रिक्स देशों तथा दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है. अप्रैल-अगस्त के दौरान भारत का ब्रिक्स देशों को एक्सपोर्ट 13% बढ़कर 34.5 अरब डॉलर हो गया. इसका मतलब यह है कि भारत के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी अब महत्वपूर्ण बाजार बनती जा रही हैं.

व्यापार के आंकड़ों पर एक नजर

विवरण	अगस्त 2025 (अरब डॉलर)	अगस्त 2026 (अरब डॉलर)	सालाना बदलाव
कुल निर्यात	27.22	43.81	+26%
कुल आयात	61.96	70.04	+14%
व्यापार घाटा	27.20	26.86	मामूली कमी
सोने का आयात	5.40	2.30	-57.7%

ब्रिक्स देशों को निर्यात

इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम सेक्टर का बड़ा योगदान : ट्रेड डेटा पर जानकारी देते हुए कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत के एक्सपोर्ट में लगातार सकारात्मक रुझान बना हुआ है. इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर ने निर्यात को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है.

एआई+ स्मार्टफोन का सर्विस नेटवर्क 1,000+ टचपॉइंट्स तक पहुँचेगा

- **दिल्ली में पहला एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर और एआई+ असिस्टेंस ऐप लॉन्च करेगा**

नवभारत कनेक्ट

इंदौर, 16 सितंबर 2026: एआई+ स्मार्टफोन भारत में अपने ग्राहकों को बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस देने के लिए देशभर में अपने सर्विस नेटवर्क को 1,000+ सर्विस सेंटर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है.

इसके साथ ही, इस दिवाली दिल्ली में अपना पहला एक्सक्लूसिव एआई+ सर्विस सेंटर भी शुरू करेगा. अपने फिजिकल सर्विस नेटवर्क के विस्तार के साथ, ब्रांड एआई+ असिस्टेंस ऐप भी पेश कर रहा है. यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ डिवाइस सपोर्ट, सर्विस बुकिंग, टिकट ट्रैकिंग और डिवाइस में आने वाली समस्याओं को दूर करने से जुड़ी मदद जैसी सभी सुविधाएँ एक ही जगह मिलेंगी. इस विस्तार के तहत मौजूदा 800+ सर्विस सेंटर के नेटवर्क में 200+ नए सर्विस सेंटर जोड़े जाएँगे. इससे देशभर में ब्रांड की आफ्टर-सेल्स पहुँच और बढ़ेगी. फिजिकल और डिजिटल विस्तार का उद्देश्य एआई+ ग्राहकों के लिए सर्विस को और आसान बनाना है.

यूपीआई के हर ग्राहक को नहीं लगेगा एमडीआर चार्ज

- **नए नियम से उठे हर उस सवाल का जवाब जो आप जानना चाहते हैं**
- **ग्राहक और छोटे दुकानदारों के लिए यूपीआई भुगतान रहेगा मुफ्त**

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 16 सितम्बर. चाय-पान, सब्जी, बिजली बिल, पेट्रोल, बीमा, टिकट, शॉपिंग पर भी क्या फीस लगेगी. क्या 2,000 रुपये से ज्यादा के हर पेमेंट पर 0.4% एमडीआर चार्ज लगेगा. 3,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 12 रुपये, 10,000 रुपये पर 40 रुपये और 75 हजार या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम चार्ज 300 रुपये लगेंगे. क्या इसके बाद राशि बढ़ने पर भी चार्ज बढ़ेगे. ऐसे कई प्रश्न यूपीआई पर लागू हुए नए नियमों के बाद हर उपयोगकर्ता के मन में उठ रहे हैं. नवभारत ऐसे सभी सवालों के जवाब पाठकों के लिए विशेषज्ञों के हवाले से लेकर आया है.

सवाल: नया एमडीआर नियम क्या है?

जवाब: 15 अक्टूबर 2026 से कुछ व्यक्ति-से-व्यापारी यानी पी2एम यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगेगा. 2,000 रुपये से ऊपर के सामान्य मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% एमडीआर होगा. ग्राहक से यह चार्ज नहीं लिया जाएगा.

सवाल: एमडीआर क्या होता है?

जवाब: एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट. यह डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी से लिया जाने वाला चार्ज है, जो बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और यूपीआई ऐप से जुड़े नेटवर्क के बीच बांटा जाता है.

सवाल: क्या सभी ग्राहक पर टैक्स है?

जवाब: नहीं. यह न टैक्स है, न ग्राहक से सरकार या एनपीसीआई द्वारा लिया जाने वाला चार्ज.

सवाल: पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा?

जवाब: नहीं. पी2पी पर ट्रांसफर हर रकम पर मुफ्त रहेगा.

सवाल: 2,000 रुपये से ऊपर ग्राहक को कितना देना होगा?

जवाब: ग्राहक को कुछ नहीं देना होगा. 0.4% एमडीआर मर्चेंट पर लागू होगा.

सवाल: मर्चेंट के लिए दर कितनी है?

जवाब: 2,000 रुपये से ऊपर के सामान्य पी2एम पेमेंट पर 0.4%. 3,000 रुपये पर 12 रुपये और 50,000 रुपये पर 200 रुपये एमडीआर होगा.

सवाल: क्या अधिकतम सीमा भी है?

जवाब: 75,000 रुपये या उससे अधिक की मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 300 रुपये होगा.

सवाल: 75,000 रुपये पर कैप की जरूरत क्यों?

जवाब: कैप के कारण 75,000 रुपये के बाद रकम बढ़ने पर एमडीआर 300 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ेगा.

सवाल: क्या छोटे दुकानदारों को भी एमडीआर भरना पड़ेगा?

जवाब: नहीं. छोटे मर्चेंट और माइक्रो-एंटरप्राइज के लिए जीरो-एमडीआर सुरक्षा जारी रहेगी.

सवाल: छोटे मर्चेंट से क्या मतलब है?

जवाब: क्यूआर से महीने में 1 लाख रुपये तक यूपीआई भुगतान लेने वाले छोटे विक्रेताओं को छूट मिलेगी.

सवाल: चाय वाले, फल वाले या सब्जी विक्रेता को पेमेंट करने पर क्या होगा?

जवाब: ग्राहक से कोई चार्ज नहीं होगा. छोटा मर्चेंट होने पर जीरो-एमडीआर व्यवस्था रहेगी. 10 से 500 रुपये के पेमेंट में बदलाव नहीं होगा.

सवाल: फोनपे, गूगल पे, पेटीएम ग्राहक से प्लेटफॉर्म फीस ले सकते हैं?

जवाब: नहीं. ग्राहक के लिए यूपीआई उपयोग मुफ्त रखने की बात स्पष्ट की गई है.

सवाल: किन कारोबारों पर सामान्य 0.4% एमडीआर नहीं लगेगा?

जवाब: रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों को विशेष राहत दी गई है. 2,000 रुपये से ऊपर योग्य पेमेंट पर 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर होगा.

सवाल: पेट्रोल पंप पर 2,000 रुपये से ऊपर यूपीआई पेमेंट का क्या नियम है?

जवाब: 2,000 रुपये तक एमडीआर शून्य रहेगा. इससे ऊपर योग्य भुगतान पर मर्चेंट के लिए 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर होगा.

सवाल: क्या बीमा प्रीमियम पर भी यही राहत मिलेगी?

जवाब: 2,000 रुपये से ऊपर के योग्य बीमा भुगतान पर 0.4% की जगह 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर.

सवाल: रेलवे टिकट या टेलीकॉम बिल भरने पर क्या बदलेगा?

जवाब: ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. 2,000 रुपये से ऊपर के योग्य पेमेंट में मर्चेंट-साइड एमडीआर 5 रुपये फ्लैट होगा.

सवाल: कृषि इनपुट को छूट, इसका क्या मतलब है?

जवाब: कृषि इनपुट को विशेष क्षेत्र में रखा गया है. इसमें बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़े जरूरी उत्पाद शामिल हो सकते हैं. अंतिम श्रेणी मर्चेंट कोड से तय होगी.

सवाल: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के पेमेंट पर दर क्या है?

जवाब: म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉकब्रोकर और डीलर से जुड़े योग्य पेमेंट पर एमडीआर 0.02% होगा. अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी.

सवाल: कैपिटल मार्केट के लिए दर कितनी है?

जवाब: योग्य कैपिटल मार्केट पेमेंट पर 0.02% एमडीआर रखा गया है.

सवाल: 1 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड पेमेंट पर कितना एमडीआर बनेगा?

जवाब: 0.2% के हिसाब से 1 लाख रुपये पर एमडीआर 20 रुपये होगा. यह ग्राहक के बजाय मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम पर लागू होगा.

सवाल: एमडीआर का पैसा किसके पास जाएगा?

जवाब: रकम बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और यूपीआई ऐप प्रदाता जैसे इकोसिस्टम भागीदारों के बीच बांटी जाएगी. इसे सरकार या एनपीसीआई की सीधी आय नहीं बताया गया है.

सवाल: क्या ज्यादातर यूपीआई पेमेंट पर असर नहीं पड़ेगा?

जवाब: वित्त मंत्रालय के अनुसार, 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट और जीरो-एमडीआर छोटे मर्चेंट व्यवस्था के कारण लगभग 96% पी2एम लेनदेन अप्रभावित रहेंगे.

सवाल: क्या मर्चेंट सामान की कीमत बढ़ाकर एमडीआर ग्राहक से वसूल सकता है?

जवाब: मर्चेंट को एमडीआर ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. चार्ज मांगे जाने पर बिल या स्क्रीनशॉट संभालकर ऐप, बैंक या शिकायत चैनल पर शिकायत की जा सकती है.

इंडियन बैंक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित

- **नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मिला सम्मान**

नवभारत,जबलपुर। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक, इंडियन बैंक को नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 26 के दौरान आयोजित हिंदी दिवस समारोह में वर्ष 25-26 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडियन बैंक को यह पुरस्कार 'राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ निष्पादन' करने के लिए लगातार तीसरे वर्ष प्राप्त हुआ है।

शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक ने नवी मुंबई के सिडको एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय छठे अभा राजभाषा सम्मेलन के हिन्दी दिवस समारोह में गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार एवं नित्यानन्द राय के कर कमलों से सचिव, राजभाषा विभाग, अंशुली आर्या की गरिमामयी उपस्थिति में यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर इंडियन बैंक द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल पुस्तक 'मैं दिल्ली हूँ' का लोकार्पण भी किया गया। यह पुरस्कार बैंक में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन और बैंकिंग कामकाज में राजभाषा हिंदी को लागू करने में बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। सम्मेलन के दूसरे दिन चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं) के संयोजक इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै को अपने कार्यक्षेत्र में संघ की राजभाषा नीति के उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन के लिए 'नराकास राजभाषा सम्मान' के तहत 'सर्वश्रेष्ठ श्रेणी' में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक वी.एन. माया एवं नराकास के सदस्य सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने ग्रहण किया। वहीं कांचीपुरम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक के रूप में इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, कांचीपुरम एवं पुदुच्चेरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक के रूप में इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय पुदुच्चेरी को संघ की राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय निष्पादन के लिए 'नराकास राजभाषा सम्मान' के तहत सम्मानित किया गया। कांचीपुरमको प्राप्त यह पुरस्कार इंडियन बैंक, कांचीपुरम अंचल के अंचल प्रबंधक एवं नराकास अध्यक्ष गोपा कुमार जी. एस. और नराकास के सदस्य सचिव व वरिष्ठ प्रबंधक सूरज प्रसाद साव ने ग्रहण किया। पुदुच्चेरी को प्राप्त यह पुरस्कार इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय में राजभाषा विभाग के सहायक महाप्रबंधक राजेश कुमार सिंह और नराकास के सदस्य सचिव सुमित साव ने ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुंबई के क्षेत्र महाप्रबन्धक प्राणेश कुमार एवं कार्यालय के स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे। इंडियन बैंक द्वारा राजभाषा प्रदर्शनी के लिए स्टाल भी लगाया गया। जिसकी सभी ने काफी सराहना की।

वेकोलि में राजभाषा पखवाड़ा-2026 का शुभारंभ

विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन

नवभारत कनेक्ट

नागपुर, 16 सितंबर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आज 'राजभाषा पखवाड़ा-2026' का विधिवत एवं भव्य शुभारंभ किया गया.

इस विशेष अवसर पर वेकोलि के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. हेमंत शरद पांडे और निदेशक (वित्त/मानव संसाधन) श्री बिक्रम घोष ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को राजभाषा पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं और दैनिक कार्य-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का संदेश दिया. वेकोलि में 'राजभाषा पखवाड़ा-2026' दिनांक 14.09.2026 से 29.09.2026 तक मनाया जाएगा.

पखवाड़े के आरंभ के पहले दिन मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सभी कार्मिकों को 'राजभाषा बैच' लगाया गया और उन्हें पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी दी गई. इसके बाद, पखवाड़े की पहली प्रतियोगिता के रूप में मुख्यालय के कल्याण सभागृह में 'चित्र पर आधारित कहानी प्रतियोगिता'

का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में वेकोलि कर्मियों ने अपनी अद्भुत रचनात्मकता और लेखन शैली का प्रदर्शन करते हुए बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मुख्यालय के साथ-साथ वेकोलि के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विभिन्न उत्साहवर्धक प्रतियोगिताओं के साथ इस पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है. प्रतियोगिता सयोजक के रूप में श्रीमती अनुपमा टेंभुर्णीकर मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन), श्री मिलिंद चहांदे, वरिष्ठ प्रबंधक (जनसंपर्क), सुश्री परिधि वर्मा, सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन/राजभाषा) एवं श्री दीपक सिंह चौहान, अनुवादक (राजभाषा) उपस्थित थे.

वर्ष 2026 के दौरान मप्र में 100 प्रतिशत दावा निपटान दर्ज किया अनुपात

नवभारत। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत दावा निपटान अनुपात दर्ज किया, जो उद्योग में अग्रणी आँकड़ा है। कंपनी की इस पहल से परिवारों को मुश्किल घड़ी में समय पर आर्थिक मदद मिली है। कंपनी ने राज्य में टर्म प्लान (रिटेल प्रोटेक्शन) व्यवसाय के संबंध में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के दौरान साल-दर-साल के आधार पर 72.10 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी दर्ज की। कंपनी ने 31 मार्च, 2026 तक राज्य में 11,93,966 लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान किया। मध्य प्रदेश में लिंक्ड, गैर-लिंक्ड और एन्युइटी व्यवसाय समेत कंपनी के बचत व्यवसाय की भी अच्छी मांग है। राज्य में 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) 6,256 करोड़ रुपए थी। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने राज्य में 31 मार्च, 2026 तक 73,100 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड दर्ज किया और पिछले सात साल में, कंपनी ने मध्य प्रदेश राज्य में अपने ग्राहकों को कुल 2,300 करोड़ के विभिन्न किस्म के लाभ प्रदान किए।

एनबीसीसी ने 66वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सीपीएसई, ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से अपनी 66वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की.

डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी ने बैठक की अध्यक्षता की और शेयरधारकों को संबोधित किया. पुनर्विकास, रियल एस्टेट, संस्थागत अवसंरचना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कंपनी द्वारा तलाशे जा रहे अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के मजबूत वित्तीय कार्य-निष्पादन, कारोबार में वृद्धि और प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला. एजीएम में डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य), श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त), श्री संजीत, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री विशाल पुरी, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती दीप्ति गंभीर, कंपनी सचिव सहित एनबीसीसी के निदेशक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे.

अपने संबोधन के दौरान, डॉ. महादेवास्वामी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन पर प्रकाश डाला. एनबीसीसी ने 13,195.89 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व दर्ज किया, जिसमें 7.52% की वृद्धि हुई, जबकि समेकित कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 33.19% बढ़कर 742.45 करोड़ रुपये रहा. एकल आधार पर, कंपनी ने 10,055.45 करोड़ रुपये की कुल आय और 703.29 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जो 47.72% की वृद्धि दर्शाता है.

समाचार विशेष

राजनीति में एक नए दलित चेहरे की एंट्री

लखनऊ, 16 सितंबर. यूपी की दलित राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक मोर्चा बनता दिख रहा है. स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद रोहिणी घावरी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में हैं.

उनका मुख्य फोकस वाल्मीकि समाज को एकजुट करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 21 विधानसभा सीटों पर है, जहां वाल्मीकि मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है. इन इलाकों में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर का भी प्रभाव माना जाता है. रोहिणी वाल्मीकि समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए इन क्षेत्रों में अभियान चलाने की तैयारी में हैं. उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज को लंबे समय से मुख्य रूप से सफाईकर्मी के तौर पर देखा गया, जबकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उसकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही है. वह अगले पांच साल में किसी राज्य में वाल्मीकि समाज से मुख्यमंत्री बनाए जाने का लक्ष्य भी सामने रख रही हैं. उनकी नजर आगरा कैंट, एत्मादपुर, जसराना, फिरोजाबाद, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, गाजियाबाद, लोनी, लखनऊ की मध्य, उत्तर और पश्चिम विधानसभा सीटों के अलावा सीसामऊ, आर्यनगर, किदवईनगर, अलीगढ़ और खैर समेत 21 सीटों पर है. इन सीटों पर वह जाटव और वाल्मीकि समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाने की तैयारी में हैं.

चंद्रशेखर पर आरोप

रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शादी का वादा कर शोषण करने के आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि आर्थिक मदद करने के बावजूद सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर ने उनसे संबंध तोड़ लिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाल्मीकि समाज से होने के कारण उनकी शिकायत पर एफआईआर नहीं हुई. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का पक्ष इस खबर में शामिल नहीं है. दलित राजनीति में अब तक जाटव मतदाताओं का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है. ऐसे में वाल्मीकि समाज को अलग राजनीतिक ताकत के तौर पर लामबंद करने की कोशिश 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर नए समीकरण पैदा कर सकती है. रोहिणी सर्वसमाज को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात भी कह रही हैं.

43वां तटरक्षक कमांडर्स सम्मेलन आज से

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर भारतीय तटरक्षक बल के 43वें कमांडर्स सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 सितंबर 2026 तक तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में किया जाएगा।

यह वार्षिक शीर्ष स्तरीय सम्मेलन भारतीय तटरक्षक बल का सर्वोच्च पेशेवर मंच है, जिसमें देशभर से वरिष्ठ कमांडर एकत्रित होकर रणनीतिक, परिचालन एवं प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करेंगे। 17 सितंबर 2026 को माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ सेवा के वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित करेंगे। उनका संवाद भारतीय तटरक्षक बल को

सशक्त बनाने तथा भारत के समुद्री हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में उसकी भूमिका को और मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराएगा। सम्मेलन में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए चल रही पहलों की भी समीक्षा की जाएगी। ये पहल सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।43वां कमांडर्स सम्मेलन एक अधिक सशक्त, आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार भारतीय तटरक्षक बल के निर्माण की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारतीय तटरक्षक बल भारत के संप्रभु समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर समर्पित है।

इन विषयों पर होगा विचार-विमर्श

- वर्तमान एवं उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ।
- परिचालन तैयारियों एवं संसाधनों की तैनाती।
- क्षमता वृद्धि एवं बल के आधुनिकीकरण की रूपरेखा।
- राष्ट्रीय समुद्री रणनीति के अनुरूप संगठनात्मक प्राथमिकताएँ।

अकाली दल ने दिए नजदीक आने के इशारे

चंडीगढ़, 16 सितंबर. पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के रिश्तों को लेकर एक बार फिर नए संकेत दिखाई दे रहे हैं. करीब छह साल पहले कृषि कानूनों के मुद्दे पर भाजपा से गठबंधन तोड़ने वाला अकाली दल पिछले चार वर्षों में तीन अलग-अलग मौकों पर भाजपा के साथ खड़े होने के संकेत दे चुका है.

इसके बावजूद भाजपा की ओर से अब तक ऐसा कोई समान राजनीतिक कदम सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है. भाजपा लगातार पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी का संदेश दे रही है. अकाली दल के तीन सकारात्मक संकेतों के बावजूद भाजपा का सार्वजनिक रुख नहीं बदला है. भाजपा सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी का संदेश दे रही है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने अगस्त में पंजाब दौरे के दौरान सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने और अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी का संकेत दिया था.

विशेष | राजस्थान के दर्जनों निकायों में निर्दलीय किंगमेकर, झपट्टामार राजनीति संभावित

शुरू हुई निकाय प्रमुख बनाने की जंग

जयपुर, 16 सितंबर. राजस्थान में निकाय चुनाव नतीजे आ गए हैं. प्रदेश के 309 निकायों में हुए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. दूसरे नंबर पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस रही है. तीसरे नंबर पर निर्दलीय रहे हैं.

इन चुनावों में निर्दलियों ने झंडे गाड़ दिए हैं और बीजेपी कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है. सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर समेत जोधपुर, अजमेर और पाली जैसे नगर निगमों में महापौर की ताजपोशी में निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे. भरतपुर में तो कुल सीटों में से आधे से ज्यादा निर्दलीय जीते हैं. वहां बीजेपी केवल 20 सीटों पर ही सिमट गई. राजस्थान के 10 नगर निगमों में से सत्तारुढ़ बीजेपी को महज चार जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा निगम में स्पष्ट बहुमत मिला है. जबकि कांग्रेस को केवल एक ही निगम बीकानेर में उसके पक्ष में जनादेश मिला है. सूबे के पांच बड़े निगम जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, पाली और अलवर में बीजेपी और कांग्रेस किसी को भी साफ बहुमत नहीं मिला है. इन निगमों में निर्दलीयों की भूमिका अहम हो गई है. केवल इन पांच निगमों में ही नहीं बल्कि प्रदेश की दर्जनों नगर परिषद और नगरपालिकाओं में भी हालत कमोबेश ऐसे ही हैं.

145 निकायों में किसी को बहुमत नहीं - पांच नगर निगमों समेत प्रदेश के करीब 145 निकाय ऐसे हैं जहां किसी को भी साफ बहुमत नहीं मिला है. इन सब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नजरें निर्दलीयों पर टिकी है.